



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1415]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2009/भाद्र 16, 1931

No. 1415]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2009/BHADRA 16, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

का.आ. 2276(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलैक्ट्रॉनिक रीति में कंपनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम, “इलैक्ट्रॉनिक रीति में कंपनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम (संशोधन) स्कीम, 2009” है ।

(2) यह स्कीम, 13 सितंबर, 2009 से प्रवृत्त होगी ।

2. इलैक्ट्रॉनिक रीति में कंपनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम के उपाबद्ध ‘क’ के पैरा 4 में उपपैरा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(8) एमसीए पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क का संग्रहण और उनके वास्तविक प्रस्तुतिकरण से अभिमुक्ति ।

(क) केन्द्रीय सरकार ने, सभी संव्यवहारों को तेज करने, सेवा प्रदाय को उन्नत करने और रजिस्ट्रार कार्यालय को कागज रहित बनाने के प्रयोजन के लिए, दस्तावेजों के वास्तविक प्रस्तुतीकरण से अभिमुक्ति करने का विनिश्चय किया है। केन्द्रीय सरकार, प्ररूप सं० 1, संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, प्ररूप सं० 5 और प्ररूप सं० 44 पर संदेय स्टांप शुल्क, एमसीए पोर्टल, [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) के माध्यम से उनकी ई-फाइलिंग के समय आरंभ में ही संग्रहीत करेगी। केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की ओर से स्टांप शुल्क संग्रहीत करेगी और उसको, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के खाते में सीधे, अनुमोदित संदाय और लेखा प्रक्रिया के अनुसार भेजेगी। स्टांप शुल्क के संग्रहण के लिए प्रक्रिया 13 सितंबर, 2009 से प्रवृत्त होगी। केन्द्रीय सरकार ने, सिक्किम राज्य के सिवाय, जहां कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध विस्तारित नहीं किए गए हैं, अट्ठाईस राज्यों और सात संघ राज्यक्षेत्रों से, उनकी ओर से ई-स्टांप संस्थित करने के लिए प्राधिकार चाहा है। केन्द्रीय सरकार को केवल बाइस राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासकों से प्राधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे ही शेष बारह राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् चंडीगढ़, दमण और दीव, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, नागालैंड तथा त्रिपुरा से प्राधिकार प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार, उनकी ओर से भी स्टांप शुल्क का संग्रहण प्रारंभ करेगी।

(ख) कंपनियों को, उनके द्वारा पहले से ही क्रय कर लिए गए स्टांप पेपरों का उपयोग करने में समर्थ करने के लिए साढ़े तीन मास की संक्रमण अवधि होगी। उन राज्यों के संबंध में जिन्होंने केन्द्रीय सरकार को उनकी ओर से स्टांप शुल्क संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है, किसी कंपनी के लिए स्टांप शुल्क के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदाय को अनिवार्य बनाने के लिए 1 जनवरी, 2010 अंतिम तारीख होगी। उन राज्य के संबंध में जिनसे अभी प्राधिकार प्राप्त होना है, कंपनी, एमसीए पोर्टल के बाहर स्टांप शुल्क संदाय करना जारी रखेगी।

(ग) कंपनी, उन दस्तावेजों का, जिनका स्टांप शुल्क एमसीए पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किया गया है, वास्तविक प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाएगा।

तथापि, उन दस्तावेजों का, जिनका स्टॉप शुल्क, एमसीए पोर्टल के माध्यम से संदत्त नहीं किया गया है, कंपनी, उनकी इलैक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल फाइल करने के अतिरिक्त, एक साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी ऐसे स्टॉपिकृत दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

(घ) खंड (क) में विनिर्दिष्ट उन दस्तावेजों से भिन्न जो एमसीए पोर्टल के माध्यम से स्टॉप शुल्क के संदाय के लिए सम्मिलित नहीं किए गए हैं और जिन पर संबंधित राज्य में संदेय स्टॉप शुल्क एक सौ रुपए या उससे कम है, ऐसे स्टॉपिकृत दस्तावेजों को कंपनी द्वारा पर्यवलोकित किया जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा साक्ष्य के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाएगा तथा सिवाय उनका, जिनका धारा 621क की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन अपराध का शमन करने के लिए फाइल किया जाना अपेक्षित है, वास्तविक प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक नहीं है । तथापि कंपनी, ऐसे सम्यक् रूप से स्टॉपिकृत दस्तावेजों को, मूल रूप में, दस्तावेजों को फाइल करने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिधारित करेगी और उनका, सक्षम प्राधिकारियों की अर्थात् संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के स्टॉप कलेक्टर या रजिस्ट्रार की मांग पर निरीक्षण और सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित होगा” ।

[फा. सं. 1/04/2009-सी.एल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम, सं. का.आ. 1844(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2009

**S.O. 2276(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 610B of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Scheme for Filing of Statutory Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode, namely:-

1. (1) This Scheme may be called as the “Scheme for Filing of Statutory

Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode  
(Amendment) Scheme, 2009.

(2) This scheme shall come into force on the 13<sup>th</sup> day of September, 2009.

2. In the Scheme for Filing of Statutory Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode, in Annexre 'A', in paragraph 4, for sub-paragraph (8), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(8) Collection of Stamp Duty on documents through MCA portal and dispensation of physical submission thereof.

(a) The Central Government, for the purpose of making all transactions faster, improving service delivery and making Office of the Registrar paperless, has decided to dispense with the physical submission of documents. The Central Government shall initially collect stamp duty payable on Form No.1, Memorandum of Association, Article of Association, Form No. 5 and Form No. 44 at the time of their e-filing, through MCA portal [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in). The Central government shall collect the stamp duty on behalf of the State Governments and Union territories for specific purpose of e-filing of documents under the provision of the Companies Act, 1956 and to remit the same directly to the accounts of the State Governments and Union territories in accordance with the approved payment and accounting procedure. The procedure for collection of stamp duty shall come into force with effect from the 13<sup>th</sup> day of September, 2009. Out of twenty eight States and seven Union territories, except State of Sikkam, where the provisions of the Companies Act, 1956 are not extended, the Central Government has sought authorisation to generate e-Stamps on their behalf. The Central Government has received authorization from only twenty-two State Governments and Union territory Administrations. As soon as the authorization from the remaining twelve States and Union territories, namely,

Chandigarh, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Kerala, Mizoram, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Nagaland and Tripura is received, the Central Government shall start collection of stamp duty on their behalf also.

(b) There shall be a transition period of three and a half months to enable the companies to use their already purchased stamp papers. The 1<sup>st</sup> day of January, 2010 shall be the cut off date for a company to compulsorily make payment electronically for stamp duty in respect of the States which have authorized the Central Government to collect stamp duty on their behalf. In respect of the States from whom the authorization is yet to be received, the company shall continue to pay stamp duty outside the MCA portal .

(c) The company shall not make physical submission of documents on which stamp duty is paid electronically through MCA portal. However, documents on which stamp duty is not paid through MCA portal, the company shall, in addition to their electronic filing, submit physical copies of such stamped documents at the office of the Registrar also, simultaneously.

(d) Documents other than those specified in clause (a) which are not covered for payment of stamp duty through MCA portal, and on which stamp duty payable in respective State is equal to or less than one hundred rupees, such stamped documents, shall be scanned by the company and filed electronically for evidencing by the Registrar and need not be submitted physically except those required to be filed for compounding of offence under clause (a) of sub-section (4) of section 621A. However, the company shall retain such documents duly stamped in original for a minimum period of three years from the date of filing of such documents and shall be required to produce the same as

3263 48/01-2

and when the same is required for inspection and verification by the competent authorities namely, the Collector of Stamps of the respective State or Union territory or the Registrar”.

[F. No. 1/04/2009-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The principal scheme was published vide number S.O.1844 (E) dated the 26<sup>th</sup> October, 2006.